trict was maximum upto 11 ppm (parts per million)|miligram per litre against the permissible level of 1.5 ppm. Continuous use of excess fluoride in drinking water leads to dental and skeletal deformity but this does not lead to any death.

(c) 36 villages-13 in Lathi and 23 in Lilla have excess fluoride in drinking water in Amreli district.

(d) and (e) A regional water supply scheme covering 36 affected villages is being implemented through a river dam (Kalubhar). 26 villages have already been provided safe drinking water facilities from this scheme. The remaining villages are likely to be covered by the end of June, 1992. The villages having excess fluoride in drinking water are provided safe drinking water facilities through alternative sources or through defluoridation plants.

विकास परियोजनाओं में ग्रामीणों का योगदान

2095. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास परिषद के अधीन विकास परियोजनाओं में ग्रामीणों का योगदान कितने प्रतिशत है;

(ख) ग्रामीणों को अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं हैं, अब तक ग्रामीणों द्वारा कितने कापीराइट्स और पेटेंट कराये गये हैं और इस संबंध में वार्षिक औसत कितना है;

(ग) ग्रामीणों से अधिक से अधिक अनुसंधान कराने और उनके द्वारा पेटेंट कराये जाने के लिए समयबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास पत्रिकाओं के नाम अंग्रेजी से बदलकर हिन्दी में करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार को ग्रामीण विकास परिषद तथा उसके माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ग्रामीण लोगों द्वारा अनुसंधान किए जाने के बारे में कोई योजना नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, आपरेशन रिसर्च, ऑनफार्म रिसर्च तथा "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम (लेब टू लैंड प्रोग्राम) की मार्फत अनुसंधान प्रौद्योगिकी के परिणाम को किसानों तक पहुंचाया जाता है; ग्रामीण लोगों द्वारा पेटेंटों अथवा प्रतिलिप्याधिकार के बारे में कोई विशेष योजना नहीं है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय दो मासिक प्रकाशन, कुरुक्षेत्र और ग्रामीण विकास न्यूजलेटर प्रकाशित करता है। ग्रामीण जनसंख्या के काफी बड़े वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ये दोनों प्रकाशन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों के नामों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Corruption in Council for Advancement of People's Action and Rural Technology Department

2096. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of rampant corruption prevailing in the department of Council for Advancement of People's Actions and Rural Technology; and

(b) if so, what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVE-

LOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) The charges of rampant corruption against Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) have not been found to have any substance.

Sectoral allocation of budget for CAPART

2097. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the sectoral allocation of Budget for CAPART during 1990-91 and 1991-92; and

(b) what was the state-wise distribution of Budget of CAPART during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Funds are sanctioned by Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) under various schemes to Voluntary Organisations. Scheme-wise allocation of budget during the years 1990-91 & 1991-92 is given in the annexure.

[*See* Appendix CLXIII, Annexure No. 39].

(b) No State-wise allocation of funds is made by the Council. Funds are sanctioned to Voluntary Organisations in different States on the basis of the Projects received. A statement showing State-wise distribution of sanctioned projects alongwith amount during the period is enclosed at Annexure.

[*See* Appendix CLXIII, Annexure No. 40].

गांवों की दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदारी

2098. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने गांवों की दुर्दशा के लिये सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) गांव, खण्ड तथा जिला स्तर पर समन्वित विकास के लिए उपयुक्त स्व-प्रबन्ध संगठनों/निष्पादन पद्धतियों का अध्ययन और विकास करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया है कि "कानूनी जटिलताओं के अलावा सरकारी तन्त्र की बहुलता और अफसरशाही में लोगों की पहल-शक्ति को आगे नहीं आने दिया है।" कार्यदल की मुख्य सिफारिशें ये हैं :-

(1) सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

(2) मौजूदा नागरिक और विकास प्रशासन को एकीकृत करना।

(3) सहकारी समिति अधिनियम और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम को सरल बनाना।

(4) "ग्राम विकास संगमों" का गठन करना, जो गांव के सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों का प्रबन्ध करने एवं सामाजिक सुधार लाने के लिए गैर-राजनैतिक संगठन होंगे और जिनके प्रति ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

(5) कार्यदल ने केन्द्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल संस्था के सृजन करने की सिफारिश की है।